Drishti IAS

करेंट अफेयर्स छत्तीसगढ़

अगस्त (संग्रह)

2022

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

छत्तीसगढ़ **3**

- चंदखुरी, गिरौदपुरी और सोनाखान का बदलेगा नाम 3
- छत्तीसगढ़ में जुलाई माह में बेरोज़गारी देश में न्यूनतम 3
- छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैंड अथॉरिटी की बैठक 4
- रोलिंग मिलों को ऊर्जा प्रभार में 24 प्रतिशत की छूट 4
- प्रदेश में 3 साल में 2 लाख से ज़्यादा बच्चे कुपोषण से बाहर 5
- मुख्यमंत्री ने 'बस्तर टाइगर' किताब का किया विमोचन 6
- विश्व आदिवासी दिवस पर पारंपरिक खेल 'मड़ई' का आयोजन 6
- नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना का ज़िक्र 7
- 'आदि विद्रोह' सहित 44 महत्त्वपूर्ण पुस्तकों का विमोचन 8
- छत्तीसगढ़ में PESA कानून लागू 9
- टाइगर रिज़र्व में सामुदायिक वन संसाधन के अधिकार 10
- WEF ने की छत्तीसगढ़ की वन संरक्षण के लिये किये जा रहे कार्यों की सराहना 10
- मुख्यमंत्री ने प्रदेश के तीन उत्कृष्ट स्वावलंबी गौठानों को किया सम्मानित 11
- साहित्यकार लीलाधर मंडलोई को मिला वसुंधरा सम्मान 12
- मुख्यमंत्री ने 61 पत्रकारों को श्रमवीर सम्मान से किया सम्मानित 12
- आज़ादी की 75वीं वर्षगाँठ पर जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ 13
- राज्य के 422 स्कूलों में लागू होगी स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना 13
- छत्तीसगढ़ की अंकिता ने स्वतंत्रता दिवस पर यूरोप की सबसे ऊँची चोटी माउंट एलब्रूस पर फहराया तिरंगा 14
- दलहनी फसलों के अनुसंधान एवं विकास पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ 14
- नया रायपुर में विद्युत उपकरणों की टेस्टिंग के लिये क्षेत्रीय टेस्ट प्रयोगशाला की होगी स्थापना 15
- ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज़ी मुकाबले 'द जंगल रंबल' का राजधानी रायपुर में हुआ आयोजन 16
- छत्तीसगढ़ में खुलेंगे स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श महाविद्यालय 17
- कृष्ण कुंज 17
- छत्तीसगढ़ को मिला अपना पहला स्किन बैंक 18
- प्रदेश के सबसे बड़े जैन कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण 18
- राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना 19
- 'डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क' और टास्क फोर्स के प्रतिवेदनों का विमोचन 20
- छत्तीसगढ़ की ममता अहार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिये चयनित 20
- छत्तीसगढ़ का बस्तर 'बेस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन' के रूप में सम्मानित 21
- 1320 मेगावाट के नए बिजली संयंत्र लगाने के निर्देश 21
- 51वाँ महापौर परिषद सम्मेलन 22
- रायपुर के बूढ़ातालाब प्रोजेक्ट को मिला 'स्मार्ट प्रोजेक्ट' अवार्ड 22
- बाल वैज्ञानिक पीयूष की रिसर्च बुक 'वेलोसिटी मिस्ट्री' का विमोचन 23
- आपराधिक मामलों में 2021 में छत्तीसगढ़ पड़ोसी राज्यों से बेहतर स्थिति में 23

नोट :

छत्तीसगढ़

चंदखुरी, गिरौदपुरी और सोनाखान का बदलेगा नाम

चर्चा में क्यों ?

1 अगस्त, 2022 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के महापुरुषों तथा आस्था के केंद्रों को जनभावनाओं के अनुरूप नई पहचान देने के लिये रायपुर और बलौदाबाज़ार-भाटापारा ज़िलों के तीन गाँवों का नाम बदलने का निर्देश दिया है।

प्रमुख बिंदु

- जिन तीन गाँवों का नाम बदलने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है, उनमें रायपुर ज़िले का चंदखुरी तथा बलौदाबाज़ार-भाटापारा ज़िले के गिरौदपुरी और सोनाखान गाँव शामिल हैं।
- मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब भगवान श्री राम की माता कौशल्या की जन्मस्थली माने जाने वाले चंदखुरी का नाम बदलकर 'माता कौशल्या धाम चंदखुरी' कर दिया जाएगा।
- इसी तरह सतनाम पंथ के लोकप्रिय तीर्थस्थल गिरौदपुरी को 'बाबा गुरु घासीदास धाम गिरौदपुरी' कहा जाएगा और सोनाखान का नाम बदलकर 'शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोनाखान' रखा जाएगा।
- गौरतलब है कि राज्य की महत्त्वाकांक्षी 'राम वन गमन' पर्यटन सर्किट परियोजना में शामिल चंदखुरी को भगवान श्री राम की माता कौशल्या का जन्मस्थान माना जाता है। यहाँ तालाब के बीचों-बीच माता कौशल्या का मंदिर है, जो 10वीं शताब्दी में बनाया गया था।
- गिरौदपुरी सतनाम पंथ का सबसे बड़ा धार्मिक-सामाजिक केंद्र है। महानदी की कछार में स्थित बलौदाबाज़ार-भाटापारा ज़िले का यह छोटा-सा गाँव 18वीं सदी के सतनाम संत और महान समाज सुधारक बाबा गुरु घासीदास की जन्मभूमि और तपोभूमि है।
- सोनाखान में जन्में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर नारायण सिंह 1857 की क्रांति में छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद माने जाते हैं। वीर नारायण सिंह को 10 दिसंबर, 1857 को रायपुर के जयस्तंभ चौक पर अंग्रेज़ों ने फाँसी दे दी थी।

छत्तीसगढ़ में जुलाई माह में बेरोज़गारी देश में न्यूनतम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में आर्थिक गतिविधियों पर नज़र रखने वाली संस्था 'सेंटर फॉर मॉनीटरिंग ऑफ इंडियन इकॉनमी' (सीएमआईई) के द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में जुलाई माह में बेरोज़गारी दर देश में न्यूनतम 8 प्रतिशत रही, जबकि देश की औसत बेरोज़गारी दर 6.9 प्रतिशत दर्ज की गई।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि पिछले कई महीनों से छत्तीसगढ़ लगातार देश में सबसे कम बेरोज़गारी दर वाले राज्य का गौरव हासिल करता आया है। इससे पहले मई माह में छत्तीसगढ़ की बेरोज़गारी दर 7 प्रतिशत थी, जबकि तब देश की बेरोज़गारी दर 7.1 प्रतिशत दर्ज की गई थी। मार्च और अप्रैल माह में भी छत्तीसगढ़ की बेरोज़गारी दर देश में सबसे कम 0.6 प्रतिशत थी।
- सीएमआईई के नये आँकड़ों के अनुसार जुलाई माह में हरियाणा में 9 प्रतिशत, जम्मू और कश्मीर में 20.2 प्रतिशत, बिहार में 18.8 प्रतिशत, गोवा में 13.7 प्रतिशत, त्रिपुरा में 13 प्रतिशत, दिल्ली में 8.9 प्रतिशत, पंजाब में 7.7 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में 6.3 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 3.3 प्रतिशत, गुजरात में 2.2 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 2.0 प्रतिशत बेरोज़गारी दर दर्ज की गई।

नोट :

- साढ़े तीन साल पहले छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संतुलित करने वाली तथा रोजगार के नए अवसरों का सृजन करने वाली योजनाओं पर शासन का सर्वाधिक जोर रहा। सरकार बनने के तुरंत बाद किसानों को से मुक्ति तथा लंबित सिंचाई कर की माफी से इसकी शुरुआत की गई।
- इसके बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, सुराजी गाँव योजना, नरवा-गरवा-घुरवा-बाड़ी कार्यक्रम, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन किसान न्याय योजना, नई औद्योगिक नीति का निर्माण, वन तथा कृषि उपजों के संग्रहण की बेहतर व्यवस्था, उपजों का स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण तथा वैल्यू एडीशन, ग्रामीण औद्योगिक पार्कों की स्थापना, लघु वनोपजों के संग्रहण दर में वृद्धि तथा 65 तरह के लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीद, तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर में वृद्धि, मछली पालन तथा लाख उत्पादन को कृषि का दर्जा, परंपरागत शिल्पियों, बुनकरों तथा उद्यमियों को प्रोत्साहन, हर जिले में सी-मार्ट की स्थापना जैसे अनेक कदम उठाए गए।
- छत्तीसगढ़ ने अपनी रोजगार तथा आय मूलक योजनाओं का लगातार विस्तार किया है। इसी क्रम में हाल ही में गोधन न्याय योजना का विस्तार करते हुए गोबर के साथ-साथ गोमूत्र की खरीदी की भी शुरुआत की है। खरीदे गए गोमूत्र से भी खाद तथा कीटनाशकों का निर्माण किया जाएगा, जिससे रोजगार के नये अवसरों का सृजन होगा।
- गाँव-गाँव में निर्मित गोठानों को भी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में उन्नत किया जा रहा है, जहां तेल मिल, दाल मिल, मिनी राइस मिल जैसी प्रोसेसिंग इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं। गोठानों में विभिन्न उत्पादों का भी निर्माण किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैंड अथॉरिटी की बैठक

चर्चा में क्यों ?

2 अगस्त, 2022 को छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैंड अथॉरिटी की बैठक में कार्ययोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत राज्य में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध वेटलैंडों के समन्वित रूप से विकास के लिये विस्तार से चर्चा की गई।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में राज्य में वेटलैंडों के विकास के लिये कार्ययोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत प्राकृतिक रूप से उपलब्ध वेटलैंडों को शामिल करने का अहम निर्णय लिया गया।
- इस दौरान राज्य में प्राकृतिक वेटलैंडों की सूची तैयार करने के साथ-साथ उनका इन्वेंट्री आदि तैयार करने के संबंध में भी चर्चा हुई। इसके अलावा नव-गठित छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैंड अथॉरिटी के कार्य तथा राज्य के प्रमुख वेटलैंड्स के संरक्षण एवं प्रबंधन की कार्ययोजना तैयार करने हेतु विशेषज्ञ संस्थाओं के चयन आदि के संबंध में चर्चा की गई।
- बैठक में छत्तीगढ़ राज्य वेटलैंड अथॉरिटी हेतु वेटलैंड के संरक्षण एवं संवर्धन संबंधी कार्यों के लिये नवीन बजट मद सृजित करने का अनुमोदन किया गया। इसके अलावा राज्य की आर्द्रभूमि (वेटलैंड) के संरक्षण के लिये क्षेत्रीय कार्यों के संपादन हेतु ज़िलास्तरीय समितियों के गठन के संबंध में भी चर्चा हुई।
- उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में कुल 35 हज़ार 534 वेटलैंड हैं, जिनमें से 2.25 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के 7 हज़ार 711 वेटलैंड हैं तथा 2.25 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल के 27 हज़ार 823 वेटलैंड हैं। इन समस्त वेटलैंडों का क्षेत्रफल 3 लाख 37 हज़ार 966 हेक्टेयर है, जो राज्य के जियोग्राफिक एरिया का 2.5 प्रतिशत होता है।

रोलिंग मिलों को ऊर्जा प्रभार में 24 प्रतिशत की छूट

चर्चा में क्यों ?

2 अगस्त, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर जनहित को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य की स्टेंड एलोन रोलिंग मिलों को ऊर्जा प्रभार में 9 माह तक के लिये 24 प्रतिशत की विशेष छूट दिये जाने का निर्णय लिया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- छत्तीसगढ़ शासन के ऊर्जा विभाग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत रोलिंग मिलों को 1 जुलाई, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की कालावधि में खपत की गई बिजली की मात्रा पर देय ऊर्जा प्रभार में 24 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है।
- इससे छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड कंपनी को होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति हेतु देय सब्सिडी राशि का राज्य शासन द्वारा अग्रिम भुगतान किया जाएगा।
- गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा 1 अप्रैल, 2022 से लागू नई विद्युत की दरों से उत्पन्न परिस्थिति में राज्य में एचवी-4 टैरिफ संवर्ग में सम्मिलित स्टेंड एलोन रोलिंग मिलें, जो सीएसपीडीसीएल से बिजली प्राप्त कर रही हैं, को परिस्पर्धा में बनाए रखते हुए जनहित में राज्य शासन द्वारा रियायती पैकेज के तहत यह विशेष छूट प्रदान की गई है।
- उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में 175 रोलिंग मिलें हैं। रायपुर में 125 मिलें संचालित हैं। कोयला के दामों में लगातार वृद्धि और महँगी बिजली के चलते रोलिंग मिलों का संचालन प्रभावित हुआ है। रोलिंग मिलों के संचालन को बनाए रखने के लिये ऊर्जा प्रभार में छूट देकर विशेष राहत दी गई है, ताकि रोलिंग मिलों में काम करने वाले श्रमिकों को रोजगार मिलता रहे।

प्रदेश में 3 साल में 2 लाख से ज़्यादा बच्चे कुपोषण से बाहर

चर्चा में क्यों ?

3 अगस्त, 2022 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण मुक्ति के लिये शुरू किये गए 'मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान'के तहत पिछले तीन सालों में प्रदेश के लगभग दो लाख 11 हज़ार बच्चे कुपोषण के चक्र से बाहर आ गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि वर्ष 2019 में इस अभियान के शुरू होते समय प्रदेश में कुपोषित बच्चों की संख्या 4 लाख 33 हज़ार थी। इस प्रकार कुपोषित बच्चों की संख्या में 48 प्रतिशत की कमी एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
- इसके साथ ही योजना के तहत नियमित गरम भोजन और पौष्टिक आहार मिलने से प्रदेश की लगभग 85 हज़ार महिलाएँ भी एनीमिया मुक्त हो चुकी हैं।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015-16 में जारी राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण- 4 के आँकड़ों के अनुसार प्रदेश के 5 वर्ष से कम उम्र के 7 प्रतिशत बच्चे कुपोषण और 15 से 49 वर्ष की 47 प्रतिशत महिलाएँ एनीमिया से पीड़ित थीं। वर्ष 2018 में यह आँकड़ा बढ़कर 40 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार वर्ष 2016 से 2018 के मध्य कुपोषण कम होने के बजाय 2.3 प्रतिशत बढ़ गया।
- कुपोषित बच्चों में अधिकांश आदिवासी और दूरस्थ वनांचलों के थे। राज्य सरकार ने इसे चुनौती के रूप में लेते हुए 'मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान'की शुरुआत 2 अक्टूबर, 2019 से की थी। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान और संकल्पित प्रयासों का सुखद परिणाम रहा कि कुपोषण की दर में लगातार कमी आई है।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के 2020-21 में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 5 वर्ष तक बच्चों के वज़न के आँकड़े देखें तो कुपोषण की दर 4 प्रतिशत कम होकर 31.3 प्रतिशत हो गई है। यह दर कुपोषण की राष्ट्रीय दर 32.1 प्रतिशत से भी कम है।
- वज़न त्यौहार के आँकड़े देखें तो वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ में कुपोषण 37 प्रतिशत था, जो वर्ष 2021 में घटकर मात्र 19.86 प्रतिशत रह गया है। इस प्रकार कुपोषण की दर में दो वर्षों में 3.51 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।
- जुलाई 2021 में आयोजित वज़न त्यौहार में लगभग 22 लाख बच्चों का वज़न लिया गया था। इस दौरान पारदर्शी तरीके से कुपोषण के स्तर का आकलन किया गया। डाटा की गुणवत्ता परीक्षण और डाटा प्रमाणीकरण के लिये बाह्य एजेंसी की सेवाएँ ली गई थी। इसी तरह वर्ष 2022 में भी एक अगस्त से 13 अगस्त तक प्रदेश में वज़न त्यौहार मनाया जा रहा है। इसके आँकड़ों के आधार पर प्रदेश में वर्तमान कुपोषण दर का आकलन किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के माध्यम से कुपोषण मुक्ति के लिये प्रदेशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और सुपोषण को प्राथमिकता क्रम में रखते हुए इसके लिये राज्य में डीएमएफ, सीएसआर और अन्य मदों की राशि का उपयोग किये जाने की अनुमति मुख्यमंत्री ने दी है।

नोट :

- योजना के तहत कुपोषित महिलाओं, गर्भवती और शिशुवती माताओं के साथ बच्चों को गरम भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। राशन में आयरन और विटामिन युक्त फोर्टीफाइड चावल और गुड़ देकर लोगों के दैनिक आहार में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को दूर करने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक रेडी टू ईट और स्थानीय उपलब्धता के आधार पर पौष्टिक आहार देने की भी व्यवस्था की गई है।
- महिलाओं और बच्चों को फल, सब्ज़ियों सहित सोया और मूंगफली की चिक्की, पौष्टिक लड्डू, अंडा सहित मिलेट्स के बिस्कुट और स्वादिष्ठ पौष्टिक आहार के रूप में दिया जा जा रहा है। इससे बच्चों में खाने के प्रति रुचि जागने से कुपोषण की स्थिति में सुधार आया है।
- प्रदेश में कुपोषण मुक्ति के लिये विभिन्न विभागों के साथ योजनाओं को एकीकृत कर समन्वित प्रयास किये गये हैं। मुख्यमंत्री हाट बाज़ार क्लिनिक योजना और मलेरिया मुक्त अभियान, दाई-दीदी क्लिनिक योजना के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार दिया गया है। इससे तेजी से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ कुपोषण स्तर में सुधार देखा जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने 'बस्तर टाइगर' किताब का किया विमोचन

चर्चा में क्यों ?

4 अगस्त, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में शहीद स्वर्गीय महेंद्र कर्मा की जयंती की पूर्व संध्या पर उनके जीवन पर आधारित किताब 'बस्तर टाइगर' का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- लेखकद्वय कुणाल शुक्ला व प्रीति उपाध्याय द्वारा लिखी गई इस किताब में बस्तर टाइगर के नाम से लोकप्रिय शहीद महेंद्र कर्मा के जीवन के अनछुए पहलुओं को साझा किया गया है।
- इस किताब के माध्यम से शहीद महेंद्र कर्मा के आदिवासियों के विकास के प्रति उनकी सोच और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी गहरी आस्था को पाठकों के समक्ष रखा गया है।
- शहीद महेंद्र कर्मा, गांधी-नेहरू के विचारों से प्रेरित रहे। उन्होंने आजीवन बस्तर में शांति के लिये प्रयास किया। किताब में शहीद महेंद्र कर्मा के सलवा जुडूम को लेकर विचार पहली बार पाठकों के सामने प्रस्तुत किये गए हैं।
- गौरतलब है कि महेंद्र कर्मा छत्तीसगढ़ कॉन्ग्रेस के नेता थे। वह 2004 से 2008 तक छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। 2005 में उन्होंने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सलवा जुडूम (Salwa Judum) आंदोलन के आयोजन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह राज्य गठन के बाद से अजीत जोगी सरकार कैबिनेट में उद्योग और वाणिज्य मंत्री थे।
- 5 मई, 2013 को सुकमा में कॉन्ग्रेस द्वारा आयोजित परिवर्तन रैली से लौटते समय दरभा घाटी में महेंद्र कर्मा, तत्कालीन कॉन्ग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, विधायक उदय मुदलियर समेत 28 कॉन्ग्रेसी नेताओं की नक्सलियों ने हमला कर हत्या कर दी थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी।

विश्व आदिवासी दिवस पर पारंपरिक खेल 'मड़ई' का आयोजन

चर्चा में क्यों ?

4 अगस्त, 2022 को छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 7 और 8 अगस्त को विशेष रूप से संरक्षित जनजातियों के पारंपरिक खेल 'मड़ई' का आयोजन राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा में किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- खेल मड़ई में विभिन्न जनजातीय समुदाय द्वारा पारंपरिक रूप से खेले जाने वाले खेल, जैसे- तीरंदाजी, गुलेल, मटका दौड़, गिल्ली-डंडा, गेड़ी-दौड़, भौंरा, फुगड़ी (बालिका वर्ग), बिल्ला (बालिका वर्ग), कबड्डी, रस्साखींच, सक्तल (पिठुल), भारा दौड़, बोरा-दौड़, सुई-धागा दौड़ (बालिका वर्ग), मुदी लुकावन (गोटी लुकावन), तीन टंगड़ी दौड़ तथा नौकायन (वयस्क वर्ग के लिये) आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।

नोट :

- आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में बालक एवं बालिकाओं के लिये दो वर्ग 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग और खुली प्रतियोगिता के अंतर्गत 18 वर्ष एवं उससे अधिक की महिला और पुरुष के लिये पारंपरिक रूप से खेले जाने वाले खेल प्रतियोगिताएँ आयोजित होंगे।
- ज़िलास्तर पर अभिकरण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी विकासखंडों से खेलवार विशेष संरक्षित जनजातीय समुदायों से प्रवेश आमंत्रित किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि ज़िलों में 22 से 28 जुलाई तक खेल प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई थीं। ज़िला स्तर से चयन के बाद 17 ज़िले के लगभग 700 प्रतिभागी इस राज्यस्तरीय आयोजन में शामिल होंगे।

नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना का ज़िक्र

चर्चा में क्यों ?

7 अगस्त, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की सातवीं बैठक में प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना का ज़िक्र किया।

प्रमुख बिंदु

- नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की सातवीं बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने बैठक से संबंधित एजेंडा बिंदुओं के अतिरिक्त राज्यहित से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और विषयों पर अपनी बात रखी।
- बैठक में प्रधानमंत्री ने विशेषकर गोधन न्याय योजना का ज़िक्र करते हुए कहा कि गोबर से तैयार हो रहे वर्मी कंपोस्ट खेतों की उत्पादकता बढ़ाने में सहायक है, यह किसानों के हित में अच्छी योजना है।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले साढ़े तीन वर्षों में नीति आयोग ने प्रदेश के आकांक्षी ज़िलों के बेहतर प्रदर्शन की सराहना की है। छत्तीसगढ़ अनाज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिये 'राजीव गांधी किसान न्याय योजना', 'मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना'लागू करने के साथ ही 'छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन'गठित किया गया है।
- मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि फसल विविधीकरण एवं दलहल, तिलहन का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिये नवीन विकसित फसल किस्मों के नि:शुल्क बीज मिनी किट एवं ब्रीडर सीड बड़े पैमाने पर कृषि अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने चाहिये।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के संबंध में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में इस दिशा में कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। स्वामी आत्मानन्द उत्कृष्ट अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल की स्थापना सहित अच्छी गुणवत्ता की अधोसंरचना, उपकरण, शैक्षिक तथा पाठ्यसहगामी गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है।
- नगरीय प्रशासन पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने लगातार तीन वर्षों से राज्य स्वच्छ सर्वेक्षण में बाजी मारी है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में बेहतर कार्य किये गए हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि शहरों के निकट स्थित ग्रामीण क्षेत्रों एवं 20 हज़ार से कम आबादी के शहरों में मनरेगा लागू किया जाए।
- उन्होंने बैठक में जीएसटी क्षतिपूर्ति का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि जीएसटी कर प्रणाली से राज्यों को राजस्व की हानि हुई है, आगामी वर्ष में राज्य को लगभग 5000 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि की भरपाई की व्यवस्था केंद्र द्वारा नहीं की गई है, इसलिये जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान को जून 2022 के पश्चात् भी आगामी 05 वर्षों के लिये जारी रखा जाए।
- इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विगत 3 वर्षों के केंद्रीय बजट में छतीसगढ़ को केंद्रीय करों में हिस्से की राशि 13,089 करोड़ रुपए कम प्राप्त हुए हैं, जिससे राज्य के संसाधनों पर अत्यधिक दबाव की स्थिति निर्मित हुई है। केंद्रीय करों के हिस्से की राशि पूर्णत: राज्य को दी जाए।
- मुख्यमंत्री ने कोल ब्लॉक कंपनियों से कोल उत्खनन पर 295 रुपए प्रति टन के मान से केंद्र के पास जमा राशि 4,140 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को शीघ्र देने की मांग की। राज्य का लगभग 65 प्रतिशत खनिज राजस्व का स्रोत प्रदेश में संचालित लौह अयस्क खानें हैं। उन्होंने कोयला एवं अन्य मुख्य खनिजों की रॉयल्टी की दरों में संशोधन का अनुरोध किया।

नोट :

- मुख्यमंत्री ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा पर होने वाला व्यय केंद्र शासन द्वारा वहन किया जाना चाहिये। नक्सल उन्मूलन के लिये राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती पर हुए सुरक्षा व्यय 11 हज़ार 828 करोड़ रुपए को केंद्र सरकार द्वारा वहन करते हुए राज्य को इस बकाया से मुक्त किया जाए।

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के वनांचल 10 आकांक्षी ज़िलों में 5 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में वन संरक्षण अधिनियम के तहत छूट देने का भी आग्रह किया। इसके साथ ही उन्होने नवीन पेंशन योजना में जमा राशि की वापसी, जूट बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित करने सहित अन्य लंबित मांगों पर शीघ्र कार्रवाई का अनुरोध किया।

'आदि विद्रोह' सहित 44 महत्त्वपूर्ण पुस्तकों का विमोचन

चर्चा में क्यों ?

9 अगस्त, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में आदिम जाति अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रकाशित 'आदि विद्रोह'एवं 44 अन्य पुस्तकों का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में वन अधिकार के प्रति ग्राम सभा जागरूकता अभियान के कैलेंडर, अभियान गीत तथा सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (चारगाँव ज़िला धमतरी) के वीडियो संदेश का भी विमोचन किया।
- आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जल-जंगल-ज़मीन शोषण, उत्पीड़न से रक्षा एवं भारतीय स्वतंत्रता के लिये समय-समय पर आदिवासियों द्वारा किये गए विद्रोहों एवं देश की स्वतंत्रता हेतु विभिन्न आंदोलनों में अग्रणी भूमिका निभाने वाले वीर आदिवासी जननायकों की शौर्य गाथा को प्रदर्शित करने आदि विद्रोह, छत्तीसगढ़ के आदिवासी विद्रोह एवं स्वतंत्रता संग्राम के आदिवासी जननायक पुस्तिका तैयार की गयी है।
- इस पुस्तक में 1774 के हलबा विद्रोह से लेकर 1910 के भूमकाल विद्रोह एवं स्वतंत्रता पूर्व तक के विभिन्न आंदोलन में जिनमें राज्य के आदिवासी जननायकों की भूमिका का वर्णन है।
- इस कॉफीटेबल बुक का अंग्रेज़ी संस्करण The Tribal Revolts Tribal Heroes of Freedom Movement and the Tribal Rebellions of Chhattisgarh के नाम से प्रकाशित किया गया है।
- आदिवासी व्यंजन: राज्य के उत्तरी आदिवासी क्षेत्र, जैसे- सरगुजा, जशपुर, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपूर आदि, मध्य आदिवासी क्षेत्र, जैसे- रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, कबीरधाम, राजनांदगाँव, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी एवं दक्षिण आदिवासी क्षेत्र, जैसे- कांकेर, कोंडागाँव, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा एवं बीजापुर ज़िलों में निवासरत् जनजातियों में उनके प्राकृतिक पर्यावास मंर उपलब्ध संसाधनों एवं उनकी जीवन शैली को प्रदर्शित करने वाले विशिष्ट प्रकार के व्यंजन एवं उनकी विधियाँ अभिलेखीकृत की गई हैं।
- छत्तीसगढ़ की आदिम कला: छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर मध्य एवं दक्षिण क्षेत्र के ज़िलों में निवासरत् जनजातीय समुदायों में उनके दैनिक जीवन की उपयोगी वस्तुओं, घरों की दीवारों में उकेरे जाने वाले भित्ति चित्र, विशिष्ट संस्कारों में प्रयुक्त ज्यामितीय आकृतियाँ आदि सदैव आदिकाल से जनसामान्य के लिये आकर्षण का विषय रही हैं। इनमें सामान्य रूप से दीवारों व भूमि पर बनाए जाने वाली कलाकृति, बांस व रस्सी से निर्मित शिल्पाकृति एवं महिलाओं के शरीर में गुदवाई जाने वाली गोदनाकृति या डिज़ाइनों के स्वरूप तथा उनके पारंपरिक ज्ञान को अभिलेखीकृत किया गया है।
- छत्तीसगढ़ के जनजातीय तीज-त्योहार: राज्य के उत्तरी क्षेत्र की पहाड़ी कोरवा जनजाति का कठौरी व सोहराई त्योहार, उरांव जनजाति का सरहुल व करमा त्योहार, खैरवार जनजाति का बनगड़ी व जिवतिया त्योहार आदि, मध्य क्षेत्र की बैगा जनजाति का छेरता व अक्ती त्योहार, कमार जनजाति का माता पहुँचानी व अक्ती त्योहार, बिंझवार जनजाति का ज्योतियाँ व चउरधोनी त्योहार, राजगोंड जनजाति का उवांस व नवाखाई त्योहार आदि, राज्य के दक्षिण क्षेत्र या बस्तर संभाग की अबुझमाड़िया जनजाति का माटी तिहार व करसाड़ त्योहार, मुरिया जनजाति का कोहकांग व माटी साड त्योहार, हलबा जनजाति का बीज बाहड़ानी व तीजा चौथ एवं परजा जनजाति का अमुस या हरेली, बाली परब त्योहार के सदृश्य राज्य की अन्य जनजातियों के भी त्योहारों का अभिलेखीकरण किया गया है।

नोट :

- मानवशास्त्रीय अध्ययन: राज्य की 9 जनजातियों, यथा- राजगोंड़ धुरवा, कंडरा, नागवंशी, धांगड़, सौंता, पारधी, धनवार एवं कोंध जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन पुस्तक तैयार की गई, जिसमें जनजातियों की उत्पत्ति, सामाजिक संगठन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन एवं सामाजिक संस्कार आदि का वर्णन किया गया है।
- मोनोग्राफ अध्ययन: राज्य की जनजातियों की जीवन-शैली से संबंधित 21 बिंदुओं पर मोनोग्राफ अध्ययन किया गया है, जिसमें गोंड, हलबा, पहाड़ी कोरवा, कमार, मझवार तथा खड़िया जनजातियों का प्रथागत कानून, उरांव का सरना उत्सव, उरांव जनजाति में सांस्कृतिक परिवर्तन, दंतेवाड़ा की फागुन मड़ई, नारायणपुर की मावली मड़ई, घोटपाल मड़ई, भंगाराम जात्रा, बैगा गोदना, भुजिया गोदना, भुंजिया जनजाति का लाल बंगला, कमार जनजाति में बांस बर्तन निर्माण, कमार जनजाति में हाट बाजार, बैगा जनजाति में हाट बाजार, खैरवार जनजाति में कत्था निर्माण विधि एवं सरगुजा संभाग में हड़िया एवं मंद निर्माण विधि संबंधी प्रकाशन किये गए हैं।
- भाषा बोली: राज्य की जनजातियों में प्रचलित उनकी विशिष्ट बोलियों के संरक्षण के उद्देश्य से सादरी बोली में शब्दकोष एवं वार्तालाप संक्षेपिका, दोरली बोली में शब्दकोष एवं वार्तालाप संक्षेपिका, गोंडी बोली में शब्दकोष एवं वार्तालाप संक्षेपिका, गोंडी बोली दंडामी माड़िया में शब्दकोष एवं वार्तालाप संक्षेपिका का निर्माण किया गया है।
- प्राइमर्स: राज्य की जनजातीय बोलियों के प्रचार-प्रसार एवं प्राथमिक स्तर के बच्चों को उनकी मातृभाषा में अक्षर ज्ञान प्रदान करने हेतु प्राइमर्स प्रकाशन का कार्य किया गया है। इस कड़ी में गोंडी बोली में गिनती चार्ट, गोंडी बोली में वर्णमाला चार्ट, बैगानी बोली में वर्णमाला चार्ट, बैगानी बोली में गिनती चार्ट एवं बैगानी बोली में बारहखड़ी चार्ट आदि शामिल हैं। इसके अलावा अन्य पुस्तकों मंक राजगोंड, धुरवा, कंडरा, नागवंशी, धांगड, सौंता, पारधी, धनवार, कोंध पर पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं।

छत्तीसगढ़ में PESA कानून लागू

चर्चा में क्यों ?

9 अगस्त, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि राज्य में पेसा (Panchayat Extension of Schedule Area) अधिनियम को लेकर नियम बन चुका है, जिसे 8 अगस्त को राजपत्र में प्रकाशित भी किया जा चुका है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि 7 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पेसा कानून के प्रारूप को मंज़ूरी दी गई थी। 8 अगस्त, 2022 को राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही यह प्रदेश में लागू हो गया है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि पेसा कानून पहले से था, लेकिन इसके नियम नहीं बनने के कारण इसका लाभ आदिवासियों को नहीं मिल पा रहा था, अब नियम बन जाने से प्रदेश के आदिवासी अपने जल-जंगल-ज़मीन के बारे में खुद फैसला ले सकेंगे।
- पेसा कानून लागू होने से ग्रामसभा का अधिकार बढ़ेगा। पेसा कानून के तहत ग्रामसभा के 50 प्रतिशत सदस्य आदिवासी समुदाय से होंगे। इसमें से 25 प्रतिशत महिला सदस्य होंगी। गाँवों के विकास में निर्णय लेने और आपसी विवादों के निपटारे का भी उन्हें अधिकार होगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई, आदिवासियों को वन अधिकार के पट्टे प्रदान किये गए, जिसके तहत अभी तक पाँच लाख पट्टे वन अधिकार के तहत दिये जा चुके हैं।
- उल्लेखनीय है कि पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 या पेसा, अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिये ग्रामसभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने हेतु केंद्र द्वारा अधिनियमित किया गया था। यह कानूनी रूप से जनजातीय समुदायों, अनुसूचित क्षेत्रों के निवासियों के स्वशासन की अपनी प्रणालियों के माध्यम से खुद को नियंत्रित करने के अधिकार को मान्यता देता है, प्राकृतिक संसाधनों पर उनके पारंपरिक अधिकारों को भी स्वीकार करता है।
- पेसा ग्रामसभाओं को विकास योजनाओं की मंज़ूरी देने और सभी सामाजिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने का अधिकार देता है। इसमें नीतियों को लागू करने वाली प्रक्रियाएँ और कर्मी, लघु (गैर-लकड़ी) वन संसाधनों, लघु जल निकायों और लघु खनिजों पर नियंत्रण रखने, स्थानीय बाज़ारों का प्रबंधन, भूमि के अलगाव को रोकने और अन्य चीज़ों के साथ नशीले पदार्थों को नियंत्रित करना शामिल है।

नोट :

टाइगर रिज़र्व में सामुदायिक वन संसाधन के अधिकार

चर्चा में क्यों ?

9 अगस्त, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर एक बड़ी पहल करते हुए राज्य के दो बड़े टाइगर रिज़र्व में कोर एवं बफर क्षेत्र में वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के तहत 10 ग्रामसभाओं को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार-पत्र प्रदान किये।

प्रमुख बिंदु

- 10 ग्रामसभाओं में अचानकमार टाइगर रिज़र्व की 5 ग्रामसभाएँ एवं सीतानदी उदंती टाइगर रिज़र्व की 5 ग्रामसभाएँ शामिल हैं।
- अचानकमार टाइगर रिज़र्व की जिन 5 ग्रामसभाओं को अधिकार प्रदान किये गए हैं, वो मुंगेली ज़िला के क्षेत्र हैं, जिनमें से 4 गाँव कोर एवं 1 गाँव बफर क्षेत्र का है। इनमें महामाई को 1384.056 हेक्टेयर, बाबूटोला को 1191.6 हेक्टेयर, बम्हनी को 1663 हेक्टेयर, कटामी को 3240 हेक्टेयर एवं मंजूरहा ग्रामसभा को 661.74 हेक्टेयर पर सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्रदान किये गए।
- सीतानदी उदंती टाइगर रिज़र्व में राज्य में पहली बार एक साथ संयुक्त रूप से सामुदायिक वन संसाधन अधिकार धमतरी ज़िले के सीतानदी टाइगर रिज़र्व की तीन ग्रामसभा- लिखमा, बनियाडीह तथा मैनपुर को 1811.53 हेक्टेयर में मान्य किया गया है। उल्लेखनीय है कि तीनों ग्रामों की पारंपरिक सीमाएँ एक ही हैं, परंतु आबादी बढ़ने के कारण इन्हें तीन गाँव में विभक्त कर दिया गया था।
- टाइगर रिज़र्व के उदंती क्षेत्र का जो हिस्सा गरियाबंद ज़िले में पड़ता है, उसके बफर क्षेत्र की ग्रामसभा कुल्हाड़ीघाट को 1321.052 हेक्टेयर पर तथा ग्रामसभा कठवा को 1254.57 हेक्टेयर पर सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्रदान किये गए हैं। गौरतलब है कि ग्रामसभा कुल्हाड़ीघाट पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का गोद ग्राम है।
- इस प्रकार मुख्यमंत्री द्वारा विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कुल 12,527.548 हेक्टेयर क्षेत्रफल के सामुदायिक वन संसाधन अधिकार देकर टाइगर रिज़र्व की ग्रामसभाओं को अपने वन क्षेत्र की सुरक्षा, संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन का अधिकार दिया गया।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वन अधिकार मान्यता-पत्र के तहत आदिवासियों और वन क्षेत्रों के परंपरागत निवासियों को दी गई भूमि के विकास और उपयोग तथा उनके अधिकारों के संबंध में गाँव-गाँव में ग्राम सभाओं के माध्यम से 15 अगस्त से 26 जनवरी तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिससे वे वनों के संरक्षण और विकास में बेहतर योगदान देने के साथ वनोपजों के संग्रहण और वेल्यू एडिशन से अपनी आय में वृद्धि कर सकेंगे।

WEF ने की छत्तीसगढ़ की वन संरक्षण के लिये किये जा रहे कार्यों की सराहना

चर्चा में क्यों ?

12 अगस्त, 2022 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से वन ट्रिलियन ट्री की प्रमुख निकोल सेवाड ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण, ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों की सराहना की।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा विश्व स्तर पर वन ट्रिलियन ट्री योजना पर काम किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहा है।
- छत्तीसगढ़ में पर्यावरण संरक्षण को और कैसे बेहतर बनाया जा रहा है, इस संबंध में वन ट्रिलियन ट्री कार्यक्रम की प्रमुख निकोल सेवाड के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परिचर्चा में शामिल हुए। इस परिचर्चा में भारत में वन ट्रिलियन ट्री कार्यक्रम की संचालक रित्विका भट्टाचार्य और भैरवी जानी ने कार्यक्रम के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी।
- निकोल सेवाड ने कहा कि छत्तीसगढ़ के जंगल को अर्थव्यवस्था से जोड़ना एक महत्त्वपूर्ण कदम है, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा सकता है।
- परिचर्चा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में साइंटिफिक तरीके से वनों के संरक्षण और भूजल स्रोत को रीचार्ज करने का काम किया जा रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ के नाले 10 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक रीचार्ज हुए हैं।

नोट :

- मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में लघु वनोपजों के क्षेत्र में बेहतर काम किया जा रहा है, यदि इनके लिये लघु उद्योगों की स्थापना की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बहुत फायदा होगा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी लोग जागरूक होंगे।
- छत्तीसगढ़ में 42 फीसदी क्षेत्र जंगलों से घिरा हुआ है और राज्य में 31 फीसदी आबादी आदिवासियों की है, जो प्रमुख रूप से वनों पर निर्भर हैं। इन्हें और समृद्ध बनाने के लिये छत्तीसगढ़ सरकार व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार पट्टों का वितरण कर रही है।
- मुख्यमंत्री ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को सुझाव देते हुए कहा कि मौसम के अनुसार ही यदि हम पौधों का रोपण करें तो वनों के विकसित होने की संभावनाएँ ज़्यादा रहेंगी और ये तभी हो सकेगा, जब इनको पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नरवा योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार ने यही काम किया है। इससे नालों में पानी रीचार्ज हुआ है और पानी की पर्याप्त मात्रा होने की वजह से जंगल का दायरा बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के तीन उत्कृष्ट स्वावलंबी गौठानों को किया सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

15 अगस्त, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में आर्थिक गतिविधियों के कुशल संचालन एवं उत्कृष्ट कार्य के लिये प्रदेश के तीन स्वावलंबी गौठानों को सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- दुर्ग ज़िले के पाटन विकासखंड के केसरा गौठान, रायपुर ज़िले के आरंग विकासखंड के चटौद गौठान और कांकेर ज़िले के कोयलीबेड़ा के डोंडे, हरनगढ़ गौठान को सम्मानित किया गया।
- मुख्यमंत्री ने इन तीनों गौठानों को 50-50 हज़ार रुपए की प्रोत्साहन राशि, स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।
- इन तीनों गौठानों के गौठान समिति के अध्यक्ष क्रमश: कनक सोनी, तिलक वर्मा और विष्णु साहू ने अपने-अपने गौठानों की तरफ से यह सम्मान ग्रहण किया।
- केसरा गौठान में स्वसहायता समूह के जरिये पशुपालकों से 4900 क्विंटल गोबर खरीदकर उससे 1700 क्विंटल कंपोस्ट तैयार कर विक्रय किया गया है। केसरा गौठान में आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत महिला स्वसहायता समूहों द्वारा मुर्गीपालन, बकरीपालन, मछलीपालन, बाड़ी विकास एवं तेल पेराई मशीन जैसी गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं।
- चटौद गौठान समिति में पशुपालकों से अब तक 5500 क्विंटल गोबर खरीदकर 2200 क्विंटल कंपोस्ट तैयार कर विक्रय किया गया है। गौठान में सीता महिला संगठन मुर्गीपालन, मछलीपालन, बकरीपालन, बाड़ी विकास के साथ मशरूम उत्पादन, पापड़, आचार, बड़ी, वाशिंग पावडर आदि का उत्पादन कर रही है। सीता महिला समूह गौमूत्र खरीदी कर कीटनाशक नीमास्त्र और ब्रम्हास्त्र बना रही है, जो जैविक खेती के लिये रसायनमुक्त कीटनाशक हैं।
- डोंडे, हरनगढ़ गौठान में समूह के माध्यम से पशुपालकों से 6200 क्विंटल गोबर की खरीदी कर 2900 क्विंटल कंपोस्ट तैयार किया गया है। गौठान में स्वसहायता समूह की महिलाएँ मछलीपालन, बाड़ी विकास, मशरूम उत्पादन, दीया निर्माण जैसी आयमूलक गतिविधियाँ संचालित कर रही हैं। गौठान द्वारा वर्मी कंपोस्ट विक्रय और गोबर क्रय का कार्य भी किया जा रहा है।
- कार्यक्रम में सुराजी गाँव के अंतर्गत राज्य स्तरीय गोधन न्याय सेल में योजना के संचालन, क्रियान्वयन और समन्वय में उत्कृष्ट कार्य के लिये चार अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया।
- इन अधिकारियों में कृषि विभाग के संयुक्त संचालक रामलखन खरे, ओएसडी डॉ. मौसम मेहरा, सहायक संचालक चंदन राय और चिप्स (CHIPS) के वरिष्ठ सलाहकार नीलेश सोनी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने इन्हें प्रशस्ति-पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया।

नोट :

साहित्यकार लीलाधर मंडलोई को मिला वसुंधरा सम्मान

चर्चा में क्यों ?

14 अगस्त, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित 22वें वसुंधरा सम्मान समारोह में सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं पत्रकार लीलाधर मंडलोई को वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सम्मान समारोह कार्यक्रम में लीलाधर मंडलोई को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह तथा सम्मान निधि देकर सम्मानित किया।
- उल्लेखनीय है कि वसुंधरा सम्मान स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे की स्मृति में प्रदान किया जाता है। स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे की 46वीं पुण्यतिथि पर आयोजित वसुंधरा सम्मान का यह निरंतर 22वाँ आयोजन है।
- कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ लोक जागरण की मासिक पत्रिका कृति वसुंधरा एवं चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।
- मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे को याद करते हुए कहा कि वे ग्रामीण पत्रकारिता के पुरोधा थे। उन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में बहुत कार्य किया। वे बलि प्रथा के घोर विरोधी थे। उन्होंने अपने गाँव के मंदिर में भी बलि प्रथा बंद करा दी थी।
- गौरतलब है कि साहित्यकार लीलाधर मंडलोई का जन्म वर्ष 1954 में अविभाजित मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िला के गुढ़ी नामक गाँव में हुआ था। उनकी शिक्षा-दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई।
- लीलाधर मंडलोई दूरदर्शन और आकाशवाणी के महानिदेशक के अलावा प्रसार भारती बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं।
- मंडलोई मूलत: कवि हैं। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ की बोली की मिठास और वहाँ के जनजीवन का सजीव चित्रण है। वह लोककथा, लोकगीत, यात्रावृत्तांत, डायरी, मीडिया, पत्रकारिता तथा आलोचना लेखन की ओर प्रवृत्त हैं।

मुख्यमंत्री ने 61 पत्रकारों को श्रमवीर सम्मान से किया सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

16 अगस्त, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस के कॉन्क्लेव हॉल में आयोजित श्रमवीर सम्मान 2022-23 समारोह में जांजगीर-चांपा ज़िले के ग्राम पिहरीद में राहुल साहू के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान रिकॉर्ड 109 घंटे जीवंत कवरेज करने वाले 61 पत्रकारों को श्रमवीर सम्मान से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- इस कार्यक्रम का आयोजन भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ (प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व वेब मीडिया का राष्ट्रीय संगठन) की छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा किया गया।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिलाने के लिये जल्द पहल की जाएगी। पत्रकारों की इस मांग का अध्ययन कर शीघ्र उचित निर्णय लिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र या बजट सत्र में पत्रकार सुरक्षा कानून लाया जाएगा।
- वर्तमान में मरीज़ों के इलाज के लिये सहायता उपलब्ध कराने हेतु राज्य शासन द्वारा विभिन्न योजनाएँ संचालित की जा रही हैं।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि जांजगीर-चांपा के पिहरीद गाँव में बालक राहुल साहू के बोरवेल में गिरने की घटना के समय शासन-प्रशासन के साथ सभी लोगों (पत्रकार, व्यवसायी, समाजसेवी) ने, जिससे जो बन पड़ा सहायता की। 109 घंटे लंबे समय तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद राहुल का सकुशल लौट आना देश में इकलौता उदाहरण है।
- इस लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पत्रकारों ने अनेक कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते हुए पल-पल की सकारात्मक रिपोर्टिंग की और पूरे प्रदेश, देश और दुनिया तक सूचना पहुँचाई।

नोट :

आज़ादी की 75वीं वर्षगाँठ पर जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

15 अगस्त, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के कचहरी चौक स्थित टाउन हॉल में जनसंपर्क विभाग द्वारा आज़ादी की 75वीं वर्षगाँठ पर आयोजित छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- यह प्रदर्शनी देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले छत्तीसगढ़ के महान क्रांतिकारियों की स्मृति में आयोजित की गई है।
- इस प्रदर्शनी में आज़ादी की लड़ाई में छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारियों का योगदान, अमर क्रांतिकारियों के महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनकी जीवन यात्रा, जंगल सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन एवं स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों में उनके योगदानों को प्रदर्शित किया गया है।
- छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह, छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे कहे जाने वाले हनुमान सिंह, शहीद वीर गुंडाधुर, श्री बिरसा मुंडा, वीर सुरेंद्र साय, ठाकुर प्यारे लाल सिंह, श्री ई. राघवेंद्र राव, डॉ. खूबचंद बघेल, श्री यतियतन लाल, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, बैरिस्टर छेदीलाल, पं. माधवराव सप्रे, श्री परसराम सोनी, श्री रामप्रसाद पोटाई, महंत लक्ष्मी नारायण दास, श्री बिसाहू दास महंत, श्री धनीराम वर्मा, श्री वामनराव बलिराम लाखे, सेठ शिवदास डागा, पंडित रविशंकर शुक्ल, रायपुर की प्रथम महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राधा बाई सहित छत्तीसगढ़ के अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान को सचित्र प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के छत्तीसगढ़ प्रवास से जुड़ी जानकारी भी सचित्र प्रदर्शित की गई है।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को यह जानना बेहद ज़रूरी है कि छत्तीसगढ़ के महान क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। यह प्रदर्शनी आज की पीढ़ी को इससे अवगत कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी।
- गौरतलब है कि 15 से 21 अगस्त तक कचहरी चौक स्थित टाउन हॉल में यह प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। हमर तिरंगा अभियान पर केंद्रित फिल्म का प्रदर्शन भी प्रदर्शनी स्थल पर किया जा रहा है।

राज्य के 422 स्कूलों में लागू होगी स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना

चर्चा में क्यों ?

15 अगस्त, 2022 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के विद्यार्थियों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के लिये आगामी शिक्षा सत्र के पूर्व राज्य के 422 स्कूलों में 'स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना' लागू किये जाने की घोषणा की, जिसमें से 252 स्कूल बस्तर एवं सरगुजा संभाग में होंगे।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा कि 'स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना' से स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति आई है। विगत वर्ष राज्य सरकार ने 51 स्कूलों से यह योजना प्रारंभ की थी, जो अब बढ़ाकर 279 स्कूलों तक पहुँच चुकी है। इनमें से 32 स्कूल हिन्दी माध्यम के हैं तथा 247 स्कूलों में हिन्दी के साथ अंग्रेज़ी माध्यम में भी शिक्षा दी जा रही है।
- इस वर्ष 2 लाख 52 हज़ार 600 बच्चों ने इन स्कूलों में प्रवेश लिया है, जिनमें 1 लाख 3 हज़ार बच्चे अंग्रेज़ी माध्यम तथा 1 लाख 49 हज़ार 600 बच्चे हिन्दी माध्यम के हैं।
- इस योजना की सफलता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि अधिक-से-अधिक स्कूलों को इस योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। आगामी शिक्षा सत्र के पूर्व 422 स्कूलों में यह योजना लागू होगी, जिनमें से 252 स्कूल बस्तर एवं सरगुजा संभाग में होंगे और इनमें दंतेवाड़ा ज़िले के शत-प्रतिशत शासकीय हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूल होंगे।

नोट :

- मुख्यमंत्री ने कहा कि नवा रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बोर्डिंग स्कूल स्थापित करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है।
- बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिये राज्य सरकार ने हिन्दी के अलावा 16 स्थानीय भाषाओं में तथा 4 पड़ोसी राज्यों की भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित कराई हैं।
- 'नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक योजना' के तहत कक्षा पहली से कक्षा दसवीं तक सभी शासकीय-अशासकीय शालाओं तथा कक्षा आठवीं तक मदरसों के बच्चों को लगभग 52 लाख पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जा रही हैं।
- नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली 1 लाख 55 हज़ार छात्राओं को इस वर्ष नि:शुल्क साइकिल देने का लक्ष्य रखा गया है।
- स्कूली शिक्षा को रोज़गारमूलक बनाने के लिये उसका आईटीआई के साथ समन्वय किया गया है, ताकि स्कूली शिक्षा और आईटीआई प्रशिक्षित होने का प्रमाण-पत्र एक साथ प्राप्त हो सके। इस योजना के तहत 114 हायर सेकेंडरी स्कूलों को जोड़ा जा चुका है।
- उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिये 1 हज़ार 459 सहायक प्राध्यापकों, क्रीड़ा अधिकारियों और ग्रंथपालों की नियुक्ति की गई है। अतिथि व्याख्याताओं का मानदेय बढ़ाया गया है। सभी ज़िलों में कन्या महाविद्यालय खोलने के क्रम में मुंगेली ज़िले में नया कन्या महाविद्यालय प्रारंभ किया गया है।

छत्तीसगढ़ की अंकिता ने स्वतंत्रता दिवस पर यूरोप की सबसे ऊँची चोटी माउंट एलब्रूस पर फहराया तिरंगा

चर्चा में क्यों ?

15 अगस्त, 2022 को स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के गौरवशाली अवसर पर छत्तीसगढ़ की अंकिता गुप्ता ने यूरोपीय महाद्वीप की सबसे ऊँची चोटी माउंट एलब्रूस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दिया गया तिरंगा फहराया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यूरोप जाने से पहले विगत 3 अगस्त को युवा पर्वतारोही अंकिता को अपने निवास में राष्ट्रीय ध्वज भेंट किया था।
- गौरतलब है कि यूरोपीय महाद्वीप की सबसे ऊँची चोटी माउंट एलब्रूस (पश्चिम) की ऊँचाई 5642 मीटर (18,510 फीट) है, यहाँ का तापमान -25 से -30 डिग्री सेल्सियस तक और हवा की गति 45 से 50 किमी. तक रहती है। इन विषम परिस्थितियों में भी 15 अगस्त की सुबह 5 बजकर 43 मिनट में तिरंगा लहराकर अंकिता ने आज़ादी की 76वीं वर्षगाँठ को और यादगार बना दिया।
- चोटी पर पहुँचकर अंकिता ने राज्य सरकार के न्याय एवं सशक्तीकरण के छत्तीसगढ़ मॉडल को प्रदर्शित किया। इसके बाद उन्होंने दूसरे ही दिन 16 अगस्त को यूरोप महाद्वीप में स्थित 5621 मीटर ऊँचे माउंट एलब्रूस (पूर्व) पर्वत पर सुबह 4 बजकर 23 मिनट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया।
- अंकिता गुप्ता मूलत: कवर्धा की रहने वाली हैं। वर्तमान में वह कबीरधाम ज़िले में पुलिस विभाग के अंतर्गत आरक्षक के पद पर कार्य कर रही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा अंकिता को यूरोप में पर्वतारोहण में शामिल होने के लिये पाँच लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है।
- अंकिता गुप्ता ने कहा कि यह सफलता देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व शहीदों को समर्पित है। उन्होंने बताया कि विगत जनवरी माह में -39 डिग्री सेल्सियस पर लेह लद्दाख के यूटी कांगड़ी की 6080 मीटर ऊँची चोटी फतेह की थी। उनका लक्ष्य अब सातों महाद्वीपों की चोटी में तिरंगा फहराकर देश का मान बढ़ाना है।

दलहनी फसलों के अनुसंधान एवं विकास पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

17 अगस्त, 2022 को छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित दोदिवसीय रबी दलहन कार्यशाला एवं वार्षिक समूह बैठक का शुभारंभ किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस दोदिवसीय रबी दलहन कार्यशाला में चना, मूंग, उड़द, मसूर, तिवड़ा, राजमा एवं मटर का उत्पादन बढ़ाने हेतु नवीन उन्नत किस्मों के विकास, अनुसंधान एवं उत्पादन तकनीकी पर विचार-मंथन किया जा रहा है।
- उल्लेखनीय है कि देश में दलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये अनुसंधान एवं विकास हेतु कार्य योजना एवं रणनीति तैयार करने के लिये आयोजित इस कार्यशाला एवं वार्षिक समूह बैठक में देश के विभिन्न राज्यों के 100 से अधिक दलहन वैज्ञानिक शामिल हुए हैं।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉ. टी.आर. शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि केंद्र सरकार द्वारा भारत को दलहन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने एवं इसका आयात कम करने के लिये विशेष प्रयास किये जा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप देश में इस वर्ष 2 करोड़ 80 लाख मीट्रिक टन दलहन उत्पादन होने की संभावना है। गौरतलब है कि वर्ष 2016 में देश में 1 करोड़ 60 लाख मीट्रिक टन दलहन का उत्पादन होता था।
- उन्होंने दलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये इसकी रोगरोधी एवं उन्नतशील किस्में उगाने तथा यंत्रीकरण के उपयोग में वृद्धि करने पर ज़ोर दिया।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक डॉ. संजीव गुप्ता ने कहा कि धान के कटोरे के रूप में प्रख्यात छत्तीसगढ़ आज दलहन उत्पादन के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना रहा है। उन्होंने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा दलहनी फसलों की नवीन उन्नतशील किस्में विकसित किये जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में उगाई जाने वाली तिवड़ा की फसल खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
- इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में लगभग 11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में दलहनी फसलें ली जा रहीं हैं, जिनमें अरहर, चना, मूंग, उड़द, मसूर, कुल्थी, तिवड़ा, राजमा एवं मटर प्रमुख हैं।
- इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में दलहनी फसलों पर अनुसंधान एवं प्रसार कार्य हेतु तीन अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएँ - मुलार्प फसलें (मूंग, उड़द, मसूर, तिवड़ा, राजमा, मटर), चना एवं अरहर संचालित की जा रहीं हैं, जिसके तहत नवीन उन्नत किस्मों के विकास, उत्पादन तकनीक एवं कृषकों के खेतों पर अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन का कार्य किया जा रहा है।
- विश्वविद्यालय द्वारा अबतक विभिन्न दलहनी फसलों की उन्नतशील एवं रोगरोधी कुल 25 किस्मों का विकास किया जा चुका है, जिनमें मूंग की 2, उड़द की 1, अरहर की 3, कुल्थी की 6, लोबिया की 1, चना की 5, मटर की 4, तिवड़ा की 2 एवं मसूर की 1 किस्म प्रमुख हैं।
- कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ की प्रमुख दलहन फसल तिवड़ा की दो उन्नत किस्में विकसित की गई हैं, जो मानव उपयोग हेतु पूर्णत: सुरक्षित हैं। दलहनी फसलों में यंत्रीकरण को बढ़ावा देने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा नए कृषि यंत्र विकसित किये जा रहे हैं।
- इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ में दलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये दलहन उगाने वाले किसानों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिसके तहत धान की जगह दलहन उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति एकड़ नौ हज़ार रुपए का अनुदान दिया जा रहा है।
- उन्होंने कहा कि दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार द्वारा किसानों से अरहर एवं उड़द की खरीदी समर्थन मूल्य 6600 रुपए की जगह 8000 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर की जा रही है।
- राज्य सरकार के प्रयासों से पिछले वर्षों में राज्य में दलहन के रकबे एवं उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है और आज 11 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में दलहन फसलों की खेती की जा रही है, जिसके आगामी दो वर्षों में बढ़कर 15 लाख हेक्टेयर होने की उम्मीद है।

नया रायपुर में विद्युत उपकरणों की टेस्टिंग के लिये क्षेत्रीय टेस्ट प्रयोगशाला की होगी स्थापना

चर्चा में क्यों ?

17 अगस्त, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलूरू और छत्तीसगढ़ शासन के मध्य नवा रायपुर में विद्युत उपकरणों की टेस्टिंग के लिये राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला तथा परीक्षण केंद्र की स्थापना हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर किये गए।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- छत्तीसगढ़ ऊर्जा विभाग के सचिव अंकित आनंद और सीपीआरआई के एडिशनल डायरेक्टर बी.ए. सावले ने एमओयू पर हस्ताक्षर किये।
- नवा रायपुर में केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलूरू द्वारा स्थापित की जाने वाली क्षेत्रीय टेस्ट प्रयोगशाला मध्य भारत की सबसे बृहद् प्रयोगशाला होगी, जिसमें ट्रांसफॉर्मर, रुटीन टेस्ट, मीटर टेस्टिंग, ऑयल टेस्टिंग एवं समस्त विद्युत उपकरण के रुटीन टेस्ट की सुविधा होगी। वर्तमान में विद्युत उपकरणों को टेस्टिंग के लिये भोपाल भेजा जाता है।
- छत्तीसगढ़ में यह सुविधा उपलब्ध होने से समय एवं राजस्व में बचत होगी। इस प्रयोगशाला में विद्युत कंपनियों को टेस्टिंग में 20 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी। प्रयोगशाला के अंतर्गत ट्रेनिंग सेंटर की भी स्थापना की जाएगी, जिसमें विद्युत कंपनियों एवं निजी संस्थानों के कर्मचारियों की तकनीकी दक्षता में वृद्धि होगी।
- प्रयोगशाला तथा परीक्षण केंद्र की स्थापना हेतु अटल नगर नया रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नया रायपुर क्षेत्र के लेयर-2 ग्राम- तेंदुआ, सेक्टर-30 में 10 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है।
- प्रयोगशाला की स्थापना का कार्य 20 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से 36 माह में पूर्ण किया जाएगा।
- रायपुर में स्थापित होने वाली क्षेत्रीय टेस्ट लेबोरेटरी में हाई वोल्टेज लेबोरेटरी (इम्पल्स टेस्ट 400 केवी), रुटीन टेस्ट लेबोरेटरी फॉर ट्रांसफॉर्मर (10 एमवीए तक), टेम्परेचर राईज टेस्ट फेसिलिटी फॉर ट्रांसफॉर्मर (10 एमवीए तक), एनर्जी मीटर टेस्ट लेबोरेटरी फॉर स्मार्ट मीटर और साइबर सिक्यूरिटी टेस्ट लेबोरेटरी फॉर सबस्टेशन इक्यूपमेंट्स एंड स्मार्ट मीटर की सुविधा उपलब्ध होगी।
- उल्लेखनीय है कि केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय के अधीन गठित सार्वजनिक उपक्रम है। इस संस्थान द्वारा पावर सेक्टर के निर्माताओं एवं यूटिलिटी में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न सेवाओं, पावर सेक्टर में एप्लाइड रिसर्च को प्रोत्साहन तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दक्षता एवं विश्वसनीयता में सुधार हेतु परामर्श सेवाएँ दी जाती हैं।

ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज़ी मुकाबले 'द जंगल रंबल' का राजधानी रायपुर में हुआ आयोजन

चर्चा में क्यों ?

17 अगस्त, 2022 को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज़ी मुकाबले 'द जंगल रंबल'का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के एक मुकाबले में पेशेवर भारतीय मुक्केबाज़ विजेंदर सिंह ने घाना के एलियासु सुले को हराया।

प्रमुख बिंदु

- अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज़ी मुकाबले 'द जंगल रंबल'प्रतियोगिता में पाँच रोचक मुकाबले हुए। लाइट वेट ग्रुप में पहला मुकाबला अमेय नितिन और असद आसिफ खान के बीच हुआ। इस मुकाबले में असद ने बाजी मारी। वहीं दूसरा मुकाबला आशीष शर्मा और कार्तिक सतीश कुमार के बीच हुआ, जिसमें कार्तिक सतीश कुमार विजेता घोषित किये गए। तीसरा मैच शैकोम और गुरप्रीत सिंह के बीच हुआ। गुरप्रीत सिंह इस मैच के विजेता बने।
- मुक्केबाज़ी का चौथा मुकाबला सचिन नौटियाल बनाम फैजान अनवर के बीच हुआ। सचिन नौटियाल प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी फैजान के पंच से पस्त हुए और रिंग छोड़ बाहर चले गए। खेल के नियमों के तहत रेफरी ने फैजान को विजेता घोषित किया।
- बॉक्सिंग की इस प्रतियोगिता में सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र पेशेवर भारतीय मुक्केबाज़ विजेंदर सिंह और घाना के एलियासु सुले के बीच हुआ मुकाबला रहा। इस मैच में विजेंदर सिंह ने अपने तगड़े पंच से एलियासु सुले को मात दी। 'द जंगल रंबल'के पाँचवें और इस आखिरी मुकाबले में केवल 02 मिनट 07 सेकेंड में ही एलियासु को धूल चटा दी।
- गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ये पहला पेशेवर मुक्केबाज़ी मुकाबला है। भारत के पहले पेशेवर मुक्केबाज़ विजेंदर सिंह इस मुकाबले के लिये बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण ले रहे थे।
- उल्लेखनीय है कि 8 जून को प्रोफेशनल मुक्केबाज़ विजेंदर सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल से मुलाकात की थी और छत्तीसगढ़ में प्रोफेशनल बॉक्सिंग मैच का आयोजन करने के लिये अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री ने इस अनुरोध को स्वीकार किया था और उसी तारतम्य में मुख्यमंत्री की पहल पर राजधानी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग मुकाबला आयोजित किया गया। विजेंदर सिंह लगभग 19 महीनों के बाद रिंग में उतरे थे।

नोट :

- छत्तीसगढ़ में खेलों को बढ़ावा देने के प्रयासों के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खेल अकादमी की स्थापना की गई है और खेलों के लिये अलग से प्राधिकरण भी बनाया गया है। इससे आधारभूत सुविधाओं के विकास और खिलाड़ियों को सँवारने के काम एक साथ होंगे।
- बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में क्रिकेट का रोड सेफ्टी मैच हुआ। कई बड़े खिलाड़ियों ने अपने खेल का प्रदर्शन किया है। महिला हॉकी में पहले ही राज्य का प्रतिनिधित्व रहा है, अब कॉमनवेल्थ गेम्स में राज्य की बिटिया आरुषि कश्यप ने बैडमिंटन में मेडल जीता है। तीरंदाज़ी में भी यहाँ अनेक संभावनाएँ हैं। ऐसे आयोजनों से राज्य में खेलों को नया आयाम मिलेगा।

छत्तीसगढ़ में खुलेंगे स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श महाविद्यालय

चर्चा में क्यों ?

18 अगस्त, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में चरणबद्ध रूप से स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श महाविद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श महाविद्यालय प्रारंभ करने के संबंध में मुख्य सचिव को 10 दिनों में कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।
- मुख्यमंत्री के इस निर्णय से इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 12वीं के बाद उच्च शिक्षा के लिये अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। राज्य में ही अंग्रेज़ी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध होगी।
- प्रथम चरण में आगामी शैक्षणिक सत्र जून 2023 से राज्य के प्रमुख नगरों में कम-से-कम 10 इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोले जाएंगे। इसी तरह आगामी तीन साल में राज्य के सभी ज़िला मुख्यालयों में इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोले जाएंगे।
- गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर राज्य शासन द्वारा समाज के कमज़ोर तबके और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों को अंग्रेज़ी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिये स्वामी आत्मानंद अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल प्रारंभ किये गए हैं। विगत वर्ष 51 स्कूल प्रारंभ किये गए थे, इन स्कूलों की लोकप्रियता के कारण स्वामी आत्मानंद अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल की संख्या वर्तमान में बढ़कर 247 हो गई है।
- अब स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श महाविद्यालय प्रारंभ होने से इन स्कूलों में पढ़ाई करने वाले बच्चों के साथ-साथ अंग्रेज़ी माध्यम के निजी स्कूलों के बच्चों को अंग्रेज़ी माध्यम में उच्च शिक्षा के लिये बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
- मुख्यमंत्री ने इस योजना की सफलता को देखते हुए 15 अगस्त, 2022 को राज्य में आगामी शिक्षा सत्र के पूर्व राज्य के 422 स्कूलों में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना लागू करने की घोषणा की थी। इनमें से 252 स्कूल बस्तर एवं सरगुजा संभाग में होंगे।
- दंतेवाड़ा ज़िले के शत-प्रतिशत शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय का स्वरूप दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की शिक्षा क्रांति आने वाले समय में देश का सबसे अच्छा 'एजुकेशन मॉडल'प्रस्तुत करेगी।

कृष्ण कुंज

चर्चा में क्यों ?

19 अगस्त, 2022 को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के तेलीबांधा में विकसित किये गए 'कृष्ण कुंज'का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि जन्माष्टमी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में पूरे प्रदेश में 'कृष्ण कुंज'की शुरुआत की गई है, जिसके तहत प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के 162 चयनित स्थानों पर सांस्कृतिक, धार्मिक और जीवनोपयोगी पेड़ लगाए जाएंगे।

नोट :

- प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में न्यूनतम एक एकड़ की भूमि में सांस्कृतिक महत्त्व के जीवन उपयोगी वृक्षों का रोपण करते हुए 'कृष्ण कुंज'विकसित किया जा रहा है। इसके लिये नगरीय प्रशासन जमीन उपलब्ध कराएगी।
- इसका उद्देश्य लुप्त हो रहे धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय महत्त्व के वृक्षों का संरक्षण और आने वाली पीढ़ी को इनसे और इनके महत्त्व से परिचित कराना है।
- 'कृष्ण कुंज'में धर्मिक महत्त्व के वृक्ष बरगद, पीपल, आँवला, कदंब के साथ-साथ जीवनोपयोगी हर्रा, नीम, आम, इमली, बेर, गंगा इमली, जामुन, गंगा बेर, शहतूत, तेंदू, चिरौंजी, अनार, कैथा, नीम, गुलर, पलास, अमरूद, सीताफल तथा बेल के वृक्षों का रोपण किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ को मिला अपना पहला स्किन बैंक

चर्चा में क्यों ?

20 अगस्त, 2022 को भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) के प्रभारी निदेशक अनिर्बान दासगुप्ता ने छत्तीसगढ़ के पहले 'स्किन बैंक'का दुर्ग ज़िले के भिलाई में स्थित भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) के मुख्य अस्पताल जवाहरलाल नेहरू अस्पताल और अनुसंधान केंद्र में उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- इसके साथ ही जवाहरलाल नेहरू अस्पताल और अनुसंधान केंद्र राज्य में शव ऊतक प्रत्यारोपण के लिये पहला संस्थान होगा।
- उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी और स्किन बैंक के चिकित्सा प्रमुख डॉ. अनिरुद्ध मेने ने बताया कि यह स्किन बैंक छत्तीसगढ़ में अपनी तरह का पहला है। यह मुंबई, दिल्ली, बेगलूरू और कोच्चि के बाद देश में पाँचवा स्किन बैंक है।
- उन्होंने कहा कि केंद्र के पास सभी आवश्यक उपकरण हैं। भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) के बर्न विभाग के छह कर्मचारियों को नेशनल बर्न सेंटर, मुंबई के स्किन बैंक में प्रशिक्षित किया गया था।
- राज्य अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (SOTTO), छत्तीसगढ़ के चारसदस्यीय निरीक्षण दल की स्वीकृति के बाद इस केंद्र की शुरुआत की गई है। जारी किया गया पंजीकरण नंबर पाँच साल के लिये वैध होगा।
- बर्न यूनिट के अतिरिक्त सीएमओ डॉ. उदय कुमार ने कहा कि स्किन ट्रांसप्लांट और प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिये गंभीर रूप से झुलसे मरीज़ों के लिये स्किन बैंक वरदान साबित होगा।
- डॉ. उदय कुमार ने बताया कि आमतौर पर रोगी के पैर या पीठ की त्वचा की ऊपरी परत को हटा दिया जाता है और फिर स्किन बैंक में 50 प्रतिशत ग्लिसरॉल एवं इनक्यूबेटर में संगृहीत किया जाता है। इस त्वचा को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 5 साल तक स्टोर किया जा सकता है। साथ ही, दाता की मृत्यु के बाद भी सीमित समय के भीतर उसके शरीर से त्वचा काटी जा सकती है।

प्रदेश के सबसे बड़े जैन कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

21 अगस्त, 2022 को श्वेतांबर जैन संत ललितप्रभ एवं अन्य जैन मुनिगणों ने राजधानी रायपुर के कोतवाली चौक पर प्रदेश के सबसे बड़े 35 फीट जैन कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- कोतवाली चौक पर निर्मित इस कीर्ति स्तंभ को बनाने में राजस्थान के लाल पत्थरों का उपयोग किया गया है।
- इस कीर्ति स्तंभ में जैन धर्म के सभी प्रतीक चिह्नों का उपयोग किया गया है। स्तंभ के चारों ओर चार शेरों को भी दर्शाया गया है। गुजरात के कारीगरों ने पत्थरों पर जैन धर्म के प्रतीकों को खूबसूरती से उकेरा है।
- इस कीर्ति स्तंभ की खासियत यह है कि इसमें कहीं भी लोहे का उपयोग नहीं किया गया है। नीचे से ऊपर तक लाल पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है। आंधी, तूफान में भी यह सालों-साल सुरक्षित रहेगा।
- पहले यह स्तंभ केवल आठ फीट ऊँचाई वाला था, जिसे सड़क चौड़ीकरण के दौरान तोड़कर नया बनाया गया है।

नोट :

राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना

चर्चा में क्यों ?

20 अगस्त, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती 'सद्भावना दिवस'के अवसर पर प्रदेश के 26 लाख से अधिक किसानों को 'राजीव गांधी किसान न्याय योजना'की दूसरी किश्त और 'गोधन न्याय योजना'के हितग्राहियों के खाते में 24 करोड़ रुपए अंतरित किये।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने 'राजीव गांधी किसान न्याय योजना'की दूसरी किश्त के रूप में किसानों के खातों में 1745 करोड़ रुपए और 'गोधन न्याय योजना'के हितग्राहियों गोबर विक्रेताओं, महिला स्व-सहायता समूहों और गोठान समितियों के खातों में 5 करोड़ 24 लाख रुपए की राशि का अंतरण किया।
- 'राजीव गांधी किसान न्याय योजना'के अंतर्गत खरीफ सीजन 2021 के लिये 26 लाख 21 हज़ार 352 पंजीकृत किसानों के बैंक खातों में इनपुट सब्सिडी की द्वितीय किश्त 1745 करोड़ रुपए ऑनलाईन माध्यम से अंतरित की गई। इससे पूर्व 21 मई, 2022 को राज्य के किसानों को इस योजना की प्रथम किश्त के रूप में 1745 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था।
- द्वितीय किस्त में भुगतान की गई राशि को मिलाकर किसानों को 'राजीव गांधी किसान न्याय योजना'के शुरू होने के बाद से अब तक 14 हज़ार 665 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।
- इस योजना में खरीफ 2019 में 43 लाख किसानों को 4 किश्तों में इनपुट सब्सिडी के रूप में 5627 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इसी प्रकार खरीफ वर्ष 2020 के 20.59 लाख किसानों को 5553 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी दी गई। किसानों को फसल लागत मूल्य कम करने, उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिये इनपुट सब्सिडी की यह राशि दी जा रही है।
- इसी तरह 'गोधन न्याय योजना'के अंतर्गत पशुपालक ग्रामीणों, गोठान समितियों और महिला समूहों को कुल 5 करोड़ 24 लाख रुपए का भुगतान किया गया। इसके तहत गोबर विक्रेताओं को 64 करोड़ रुपए तथा गोठान समितियों तथा स्व-सहायता समूह को 2.60 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया।
- गोबर बेचने वाले ग्रामीणों को गोधन न्याय योजना शुरू होने के बाद से अब तक 24 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इसी तरह गोठान समितियों तथा स्व-सहायता समूह को अब तक 154.02 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 'राजीव गांधी किसान न्याय योजना'के तहत इनपुट सब्सिडी के रूप में धान उत्पादक किसानों को 9 हज़ार रुपए प्रति एकड़, सुगंधित धान तथा खरीफ की अन्य फसल लेने वाले किसानों को 10 हज़ार रुपए प्रति एकड़ और वृक्षारोपण करने वाले किसानों को 3 वर्ष तक 10 हज़ार रुपए प्रति एकड़ के मान से राशि दी जाएगी।
- उन्होंने कहा कि किसानों की कर्ज़माफी और समर्थन मूल्य के साथ इनपुट सब्सिडी देने से किसान ऋण के बोझ से उबरकर अब स्वावलंबी बन गए हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने वाले किसानों को राज्योत्सव के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में फर्टिलाइजर की गिनी-चुनी फैक्ट्रियाँ हैं। इस मामले में छत्तीसगढ़ ने काफी प्रगति की है, यहाँ गाँव-गाँव में गोठानों में वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन से उर्वरक की फैक्ट्री प्रारंभ हो गई है। वर्मी कम्पोस्ट के उपयोग से भूमि की गुणवत्ता और उर्वरता बढ़ रही है। कृषि उत्पाद ज़हरीले तत्त्वों से मुक्त हो रहे हैं। राज्य जैविक खेती की ओर बढ़ रहा है। आने वाले समय में गोठानों में बिजली भी बनाई जाएगी। गोबर से पेंट भी बनाया जा रहा है।
- कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि 'राजीव गांधी किसान न्याय योजना ' और 'गोधन न्याय योजना' से छत्तीसगढ़ की इकॉनमी में सुधार हुआ है। बैंकों का किसानों के प्रति विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इस योजना से पिछले तीन सालों से किसानों की संख्या 8 लाख बढ़ी है।

नोट :

'डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क' और टास्क फोर्स के प्रतिवेदनों का विमोचन

चर्चा में क्यों ?

20 अगस्त, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सतत् विकास लक्ष्य (SDG) के ज़िला स्तर तक स्थानीयकरण (Localization) एवं सतत् प्रभावी मॉनिटरिंग की सुनिश्चितता हेतु छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग द्वारा तैयार किये गए 'डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क (DIF)' और टास्क फोर्स के प्रतिवेदनों का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य योजना आयोग द्वारा तैयार किया गया 'छत्तीसगढ़ एसडीजी डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क (सीजी-डीआईएफ)', एक ऐसा प्रभावी प्रगति मापक फ्रेमवर्क है, जो न केवल एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में पथ-प्रदर्शक का कार्य करेगा, अपितु समस्त ज़िलों के कलेक्टरों को प्रगति में बाधक चिह्नित क्षेत्रों की पहचान कर साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में भी मदद करेगा।
- इसी प्रकार विभिन्न विभागों हेतु उपयोगी अनुशंसाओं को 'टॉस्क फोर्स रिपोर्ट'के रूप में जारी किये जाने से नवीन गतिविधियों का चयन तथा अपेक्षित क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की कई जन-कल्याणकारी योजनाओं यथा 'मध्याह्न भोजन योजना', 'मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना', 'यूनिवर्सल सार्वजनिक वितरण प्रणाली', 'मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना', 'मुख्यमंत्री हाट बाज़ार क्लिनिक योजना', 'महतारी जतन योजना', 'राजीव गांधी किसान न्याय योजना', 'सुराजी गाँव योजना', 'गोधन न्याय योजना'जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार एस.डी.जी. के उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास कर रही है।
- छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि राज्य योजना आयोग द्वारा तैयार किये गए 'डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क'के आधार पर ज़िला कलेक्टर व विभाग विभिन्न सतत् विकास लक्ष्यों की प्रगति का मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं अनुशीलन कर सकेंगे।
- 'डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क'में सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय एवं अन्य पहलुओं संबंधी कुल 82 इंडिकेटर का समावेश किया गया है।
- छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा कि राज्य सरकार के विकास एजेंडा प्रमुखत: एसडीजी के साथ परस्पर जुड़े हुए हैं। एसडीजी फ्रेमवर्क लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में संबंधित विभागों को उचित निर्णय के लिये आँकड़े आधारित साक्ष्य प्रदान करता है।

छत्तीसगढ़ की ममता अहार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिये चयनित

चर्चा में क्यों ?

25 अगस्त, 2022 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिये चयनित देश के विभिन्न राज्यों के 46 शिक्षकों के नाम की अंतिम सूची जारी की। इसमें छत्तीसगढ़ की सहायक शिक्षिका ममता अहार का नाम भी शामिल है।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु चयनित शिक्षक-शिक्षिकाओं को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 5 सितंबर, 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर वर्ष 2022 के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार के तौर पर शिक्षक-शिक्षिकाओं को 50 हज़ार रुपए की राशि और सिल्वर मेडल दिया जाएगा।
- सहायक शिक्षिका ममता अहार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिये चयनित होने वाली प्रदेश से एकमात्र शिक्षिका हैं। वे सहायक शिक्षिका के रूप में शासकीय प्राथमिक विद्यालय पी सखाराम दुबे, ज़िला रायपुर में पदस्थ हैं।
- गौरतलब है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा मंत्रालय का स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग प्रतिवर्ष 5 सितंबर को एक राष्ट्रीय समारोह का आयोजन करता है, जिसमें देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।
- पुरस्कारों के लिये शिक्षकों का चयन ऑनलाइन तीनस्तरीय चयन प्रक्रिया के ज़रिये पारदर्शी तरीके से किया जाता है।
- शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने का उद्देश्य देश के शिक्षकों के अनूठे योगदान को रेखांकित करना और ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना है, जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता व परिश्रम से न सिर्फ स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध किया है।

नोट :

छत्तीसगढ़ का बस्तर 'बेस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन' के रूप में सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

24 अगस्त, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित 19वें वार्षिक आउटलुक ट्रैवलर्स अवाड्र्स समारोह में आउटलुक ग्रुप की ओर से विभिन्न श्रेणियों में दिये जाने वाले पुरस्कार की कड़ी में आउटलुक ट्रैवलर्स अवार्ड-2022 श्रेणी में छत्तीसगढ़ के बस्तर को एक विशेष जूरी पुरस्कार के साथ 'बेस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन'के रूप में सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी. किशन रेड्डी की उपस्थिति में आउटलुक ट्रैवलर अवाड्र्स दिया गया। समारोह में छत्तीसगढ़ की ओर से यह अवार्ड पर्यटन और संस्कृति विभाग के सचिव अंबलगन पी. ने ग्रहण किया।
- उल्लेखनीय है कि इस वर्ष पुरस्कारों का 19वाँ वर्ष है। वहीं इस वर्ष आउटलुक ग्रुप के शिखर सम्मेलन का विषय 'यात्रा का तीसरा युग' निर्धारित है।
- इस वर्ष पुरस्कार का निर्णय एक शोध एजेंसी द्वारा यात्रा सर्वेक्षण तथा जूरी सदस्यों द्वारा प्रतिक्रियाओं की जाँच के आधार पर किया गया।

1320 मेगावाट के नए बिजली संयंत्र लगाने के निर्देश

चर्चा में क्यों ?

25 अगस्त, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में 1320 मेगावाट के नए बिजली संयंत्र की स्थापना के निर्देश दिये। राज्य स्थापना के बाद पहली बार इतनी क्षमता का विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- यह छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक संयंत्र होगा। इस संयंत्र की स्थापना से छत्तीसगढ़ स्टेट जनरेशन कंपनी की स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़कर 4300 मेगावाट हो जाएगी।
- मुख्यमंत्री ने अपने निवास में पावर कंपनियों की समीक्षा बैठक में भविष्य में विद्युत की मांग की आपूर्ति के लिये आवश्यक विद्युत उपलब्धता की समीक्षा की। वर्ष 2030-31 तक अपेक्षित विद्युत मांग में वृद्धि की आपूर्ति हेतु नवीन विद्युत संयंत्र की आवश्यकता होगी।
- मुख्यमंत्री ने राज्य की विद्युत उत्पादन कंपनी को कोरबा पश्चिम में उपलब्ध भूमि पर 2×660 मेगावॉट सुपर क्रिटिकल नवीन विद्युत उत्पादन संयंत्र की स्थापना हेतु समुचित कार्रवाई के निर्देश दिये।
- विद्युत उत्पादन कंपनी के प्रबंध निदेशक एनके बिजौरा ने बताया कि यह सुपर क्रिटिकल संयंत्र अत्याधुनिक तकनीक से स्थापित किया जाएगा। इससे एक ओर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, वहीं रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे।
- उन्होंने बताया कि कोरबा पश्चिम में संयंत्र स्थापना हेतु स्वयं की भूमि उपलब्ध है। साथ ही, अपेक्षित परियोजना स्थल पर कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये वर्तमान चलित उत्पादन संयंत्रों हेतु कन्वेयर बेल्ट की सुविधा भी उपलब्ध है।
- कन्वेयर बेल्ट से कोयला उपलब्धता, स्वयं की भूमि उपलब्धता तथा सुपर क्रिटिकल प्लांट होने के कारण नवीन प्रस्तावित प्लांट से उत्पादित विद्युत की दर सस्ती होना अपेक्षित है। नवीन उत्पादन संयंत्र की स्थापना से स्थानीय रोज़गार का विकास भी संभव होगा।
- मुख्यमंत्री के निर्देश उपरांत संयंत्र स्थापना के लिये आवश्यक स्वीकृतियाँ, कोयला आबंटन, जल आबंटन सहित विस्तृत डी.पी.आर. इत्यादि तैयार करने का कार्य विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा त्वरित गति से किया जाएगा, जिससे वर्ष 2030-31 तक अपेक्षित विद्युत आपूर्ति संभव हो सके।

नोट :

51वाँ महापौर परिषद सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

28 अगस्त, 2022 को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अखिल भारतीय महापौर परिषद के 51वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन परिषद के अध्यक्ष और आगरा के महापौर नवीन जैन की अगुवाई में संपन्न हुआ।

प्रमुख बिंदु

- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 26 अगस्त को इस सम्मेलन का शुभारंभ छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र का पूजन और दीप प्रज्वलन कर किया था। इस अवसर पर उन्होंने सभी महापौरों से नगर निगमों को आर्थिक स्वावलंबी बनाने का कार्य करने हेतु प्रण लेने का आह्वान किया।
- मुख्यमंत्री ने सभी महापौरों को छत्तीसगढ़ की महत्त्वाकांक्षी 'गोधन न्याय योजना'की आय के स्रोत के रूप में उपयोगिता बताते हुए कहा कि रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा के गोठान में गोबर से बिजली उत्पादन प्रारंभ किया गया है। प्रदेश में 79 लाख मीट्रिक टन गोबर प्राप्त हो रहा है, जिसमें 20 लाख मीट्रिक टन गोबर किसानों के खेतों में दिया जा रहा है, इससे भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ रही है।
- तीनदिवसीय सम्मेलन में सूरत के महापौर ने अपने वाटर प्लस शहर के बारे में बताया, वहीं इंदौर की महापौर ने देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की स्वच्छता को लेकर जानकारी दी। मोहाली और चंडीगढ़ के महापौर ने ग्रीनरी, आगरा के महापौर ने कचरे से खाद बनाना और भोपाल के महापौर ने अपने शहर के वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताया।
- महापौर परिषद के अध्यक्ष और आगरा के महापौर नवीन जैन ने बताया कि आगरा शहर से निकलने वाले 20 लाख टन कचरे से खाद बनाई, मिट्टी तैयार की गई और इसे कंस्ट्रक्शन के काम में उपयोग किया गया। अब आगरा में हर दिन निकलने वाले कचरे से बिजली बनाई जाएगी। जल्द ही इसके लिये आगरा में प्लांट लगेगा।

रायपुर के बूढ़ातालाब प्रोजेक्ट को मिला 'स्मार्ट प्रोजेक्ट' अवार्ड

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में स्मार्ट सिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से मुंबई में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ की रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के बूढ़ातालाब प्रोजेक्ट को 'स्मार्ट प्रोजेक्ट' अवार्ड से सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य परिचालन अधिकारी उज्ज्वल पोरवाल ने यह अवार्ड प्राप्त किया।
- स्मार्ट अर्बनेशन-2022 के अंतर्गत देश की 33 स्मार्ट सिटी ने इस अवार्ड के लिये अपने प्रोजेक्ट्स का नामिनेशन किया था, जिसमें रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के बूढ़ातालाब प्रोजेक्ट को अवार्ड प्रदान किया गया।
- रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा बूढ़ातालाब-स्वामी विवेकानंद सरोवर के सौंदर्यीकरण और आर्थिक गतिविधियों के संचालन व आम लोगों के आमोद-प्रमोद के लिये सुरक्षित, सुरम्य स्थल तैयार करने हेतु किये गए कार्य को स्मार्ट प्रोजेक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया।
- अवार्ड के चयन के लिये गठित ज्यूरी ने प्रोजेक्ट को आम लोगों के बेहतर जीवन स्तर और स्थानीय लोगों के आर्थिक अवसरों को बढ़ाने के लिये उपयोगी माना। ज्यूरी में आइटी कानपुर और एनआइयूए के विशेषज्ञ तथा प्रतिष्ठित कंपनियों और संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल थे।
- रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रबंध संचालक मयंक चतुर्वेदी ने बताया कि लोगों के मनोरंजन के लिये सरोवर में म्यूज़िकल व टनल फाउंटेन, आकर्षक रोशनी के साथ सरोवर के चारों ओर लैंड स्कैपिंग की गई है। साथ ही बच्चों के लिये उपयुक्त क्रीड़ा स्थल भी तैयार किया गया है।
- बूढ़ातालाब प्रोजेक्ट के अंतर्गत 28.1 हेक्टेयर जलीय क्षेत्र को विकसित किया गया है। साथ ही, 1400 वर्ग मीटर क्षेत्र में वेंडिंग ज़ोन व 700 वर्ग मीटर में फ्लोटिंग डेक विकसित किया गया है। इस क्षेत्र को हरीतिमायुक्त बनाए रखने के लिये पौधे भी रोपित किये गए हैं।

नोट :

बाल वैज्ञानिक पीयूष की रिसर्च बुक 'वेलोसिटी मिस्ट्री' का विमोचन

चर्चा में क्यों ?

29 अगस्त, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 14 वर्षीय बाल वैज्ञानिक पीयूष जयसवाल द्वारा एस्ट्रोफिजिक्स विषय पर लिखी रिसर्च बुक 'वेलोसिटी मिस्ट्री'का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- बाल वैज्ञानिक पीयूष जयसवाल ने खगोल विज्ञान में शोध कार्य के तहत इस किताब को लिखा है। इसके लिये उन्हें सबसे कम उम्र के खगोल विज्ञान लेखक का 'गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट'से नवाजा गया है।
- मुख्यमंत्री के समक्ष गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण-पत्र बाल वैज्ञानिक व लेखक पीयूष जयसवाल को प्रदान किया गया।
- उल्लेखनीय है कि गरियाबंद ज़िले के निवासी पीयूष जयसवाल ने यूएसए के मान्यताप्राप्त जर्नल 'आईजेएसईआर' से 13 साल की उम्र में पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की है।

आपराधिक मामलों में 2021 में छत्तीसगढ़ पड़ोसी राज्यों से बेहतर स्थिति में

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जारी नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की वर्ष 2021 में देश भर में घटित अपराधों के राज्यवार आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ में अपराध का स्तर नीचे गिरा है और छत्तीसगढ़ देश के अन्य राज्यों की तुलना में अपराध को कम करने में बेहतर स्थान पर है।

प्रमुख बिंदु

- सुरक्षा मूल मंत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में अपराधों में लगातार कमी आ रही है। छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2018 के पहले के आँकड़े और वर्तमान के आँकड़े ये बताते हैं कि कैसे राज्य में अपराधिक मामलों में लगातार कमी आ रही है।
- छत्तीसगढ़ पुलिस ने विभिन्न मानक प्रस्तुत किये हैं। मुख्यमंत्री की मंशा अनुरूप चिटफंड संचालकों पर कार्रवाई, आदिवासियों पर दर्ज़ प्रकरणों की केस वापसी, अपराध नियंत्रण, महिला विरूद्ध अपराधों पर त्वरित कार्रवाई, नक्सली समस्या पर प्रभावी नियंत्रण एवं नक्सलियों की गिरफ्तारी और पुलिस कर्मियों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएँ शुरू की गई हैं।
- छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस ने बेसिक, इंपेक्टफुल, विजिबल के साथ कम्युनिटी पुलिसिंग में नए आयाम प्रस्तुत किये हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस ने पूर्व के वर्षों की तुलना में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया है। इसके साथ ही पुलिस परिवार के करीब 72 हज़ार जवानों एवं उनके परिजनों के लिये विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम भी प्रारंभ किये गए हैं।
- एनसीआरबी के आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ बलात्कार के मामले में 5वें स्थान पर था, जबकि वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ का स्थान 11वाँ है। इस सूची में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र शीर्ष राज्यों में शामिल हैं।
- एनसीआरबी के आँकड़ों के अनुसार बलात्कार के प्रयास की घटनाओं में छत्तीसगढ़ 2018 तक 14वें स्थान पर था, जबकि 2021 में छत्तीसगढ़ ने अपनी स्थिति में सुधार किया है और 16वें स्थान पर है।
- एनसीआरबी के आँकड़े बताते हैं कि 2018 में छत्तीसगढ़ अपहरण के मामलों में 11वें स्थान पर था और अब इसमें एक स्थान के सुधार के साथ छत्तीसगढ़ 12वें स्थान पर है।
- छत्तीसगढ़ में डकैती जैसी बड़ी अपराधिक घटनाओं में भी कमी आई है। एनसीआरबी के आँकड़े बताते हैं कि वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ 12वें स्थान पर था, जबकि 2021 में यह 16वें स्थान पर है।
- एनसीआरबी के आँकड़ों के अनुसार हत्या के मामले में वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ देश में 15 वें स्थान पर था। वर्ष 2021 में भी छत्तीसगढ़ 15वें स्थान पर ही है। हत्या के अपराध की सूची में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है जबकि उसके बाद बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश हैं।
- हत्या का प्रयास के मामले में छत्तीसगढ़ 2018 में 17वें स्थान पर था, जबकि साल 2021 में भी 17वें स्थान पर ही है। आँकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर और महाराष्ट्र 5वें स्थान पर है। इस तरह से हत्या एवं हत्या के प्रयास जैसे अपराधों पर रोक लगाने में छत्तीसगढ़ सरकार ने सफलता हासिल की है।

नोट :